भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 927

उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा तक पहुंच और इसकी समावेशिता

†927. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा तक पहुंच और इसकी समावेशिता में सुधार लाने के लिए किसी नई नीति पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन के क्या कारण हैं; और
(ग) दिव्यांग व्यक्तियों के शैक्षिक विकास के लिए इन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक कार्रवाई की गई है या किए जाने की संभावना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयंत चौधरी)

(क) से (ग) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा क्षेत्र- के लिए एक व्यापक कार्यक्रम समग्र शिक्षा योजना शुरू है। इस योजना का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की शिक्षा को प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक एक निरंतरता में देखना है। इस योजना दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की विकलांगता की अनुसूची में उल्लिखित एक या अधिक दिव्यांग वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कवर करती है।

सीडब्ल्यूएसएन की शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा का एक समर्पित घटक है। इस घटक के माध्यम से, सामान्य स्कूलों में उनकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को उचित रूप से संबोधित करने के लिए सीडब्ल्यूएसएन को विशिष्ट छात्र उन्मुख उपायों जैसे की जाती है जिसमें पहचान और मूल्यांकन शिविर, एड्स का प्रावधान, उपकरण और सहायक उपकरण, परिवहन, स्क्राइब और एस्कॉर्ट भत्ता सहायता, ब्रेल किताबें और बड़ी प्रिंट वाली किताबें, विशेष आवश्यकताओं वाली लड़कियों के लिए वजीफा और शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की हैं । इसके अतिरिक्त, ब्लॉक स्तर पर थेराप्यूटिक उपायों के माध्यम से वैयक्तिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा में स्कूलों में बाधा मुक्त पहुंच के लिए रैंप, हैंड्रिल के साथ रैंप और दिव्यांग अनुकूल शौचालयों जैसे दिव्यांग अनुकूल अवसंरचना के निर्माण का भी प्रावधान है।

इसके अलावा, सरकार ने 10 जनवरी, 2024 को शैक्षणिक संस्थानों के लिए अभिगम्यता संहिता अधिसूचित की है और इसे 20 जून, 2024 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के नियमों में अधिसूचित किया गया है। संहिता में सीडब्ल्यूएसएन के लिए स्कूल सुविधाओं तक पहुंच की भौतिक बाधाओं और

सूचना और संचार बाधाओं की जांच है। इसके मौजूदा भवनों के लिए लागत प्रभावी समाधान के साथ बच्चों के अनुकूल मानक प्रदान की गई हैं, साथ ही नई इमारतों को राष्ट्रीय अभिगम्यता मानकों के अनुरूप बनाने के लिए तत्व का प्रावधान है।

सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की अनुसूची में संशोधन किया है और प्राथमिक स्तर पर 10:1 पीटीआर और उच्च प्राथमिक स्तर पर 15:1 पीटीआर के साथ सामान्य स्कूलों में विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को अधिसूचित किया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार सीडब्ल्यूएसएन को कई छूट/रियायतें भी प्रदान करती है जैसे स्क्राइब और प्रतिपूरक समय की सुविधा, स्क्राइब की नियुक्ति और संबंधित निर्देश, शुल्क और विशेष छूट जैसे तीसरी भाषा से छूट, विषयों के चयन में लचीलापन, वैकल्पिक प्रश्न / अलग प्रश्न आदि।

इसके अतिरिक्त, शिक्षण अधिगम सामग्री सुलभ डिजिटल रूप में आसानी से उपलब्ध है, उदाहरण के लिए दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले शिक्षार्थियों के लिए डेज़ी / ई-पब में टॉकिंग बुक्स। भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा माध्यमिक स्तर पर एक भाषा विषय के रूप में और माध्यमिक स्तर पर बधिर और कम सुनने वाले शिक्षार्थियों के लिए एक भाषा विषय के रूप में भी प्रस्तुत किया गया, अध्ययन सामग्री को आईएसएल प्रारूप में वीडियो के रूप में विकसित किया गया है, देश भर में आईएसएल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पीएम ई-विद्या टीवी चैनल पर सप्ताह में तीन बार आईएसएल में एक घंटे का लाइव टेलीकास्ट।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) एक लाइव बातचीत की श्रृंखला आयोजित कर रहा है जिसका विषय, "समावेशी कक्षाओं के लिए शिक्षण अधिगम कार्यकलाप" है। प्रत्येक एपिसोड आधे घंटे की अवधि का है जिनमें अनिवार्य आईएसएल भाषांतरकर्ता के साथ पाठ्यपुस्तकों से एक कक्षा, एक विषय और एक-अध्याय पर विचार करके समावेशी शिक्षाशास्त्र प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान फोकस किया जाता है।

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को कक्षा I से VII के लिए पाठ्यचर्या सामग्री से संबंधित आईएसएल में परिवर्तित किया गया है, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, उर्दू, अर्थशास्त्र में शब्दकोश के शब्दों को शामिल किया गया है और इन ई-विषय-वस्तु की सुसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर दीक्षा पोर्टल और पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। आईएसएलआरटीसी के सहयोग से दीक्षा पर 10,500 शब्दों का आइएसएल शब्दकोश अपलोड किया गया।

इसके अतिरिक्त, सीडब्ल्यूएसएन की पहचान में सुधार करने के लिए, सरकार ने नियमित स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन की शीघ्र जांच और पहचान के लिए प्रशस्त ऐप प्रस्तुत किया है। सीडब्ल्यूएसएन की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए हाइब्रिड मोड में निष्ठा के तहत शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

*****